बदलाव का वाहक बना नीति आयोग

अमिताभ कांत

आयोग ने न केवल अपने नाम के अनुरूप काम किया है, बल्कि भारत के कायाकल्प की कवायद को नई ऊर्जा, जोश और गतिशीलता भी प्रदान की है

वर्ष 2015 में स्थापित हुआ नीति आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे युवा संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना पुराने ढर्रे वाली केंद्रीकृत नियोजन वाली व्यवस्था को खत्म करके विकास एजेंडे को नई सोच देने के मकसद के साथ की गई थी। इसे सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने, विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने, विकास एजेंडे को पुनर्परिभाषित करने, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समाधान निकालने के लिए मंच प्रदान करने जैसे दयित्व दिए गए। इनके अलावा क्षमता निर्माण और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र की भूमिका निभाने जैसी महती जिम्मेदारियां भी इस नई नवेली संस्था को सौंपी गईं। अब चूंकि इस संस्था को अस्तित्व में आए हुए तीन साल बीत गए हैं तो आकलन करना उचित होगा कि क्या यह अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाया या फिर यह नई शैली में पुराने ढर्रे वाला ही संस्थान है। मेरी राय में तो आयोग अपनी भूमिका में पूरी तरह खरा उतरा और नीति निर्माण के मोर्चे पर व्यापक बदलावों का वाहक बना। पहला तो यही कि देश के नीतिगत परिदृश्य में आयोग ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को नई स्फूर्ति दी। विभिन्न मंचों पर परामर्श के बाद कई प्रमुख नीतिगत प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तार्किक बनाने, कौशल विकास, स्वच्छ भारत मिशन, कृषि विकास और डिजिटल भुगतान जैसे मसलों पर राज्यों के साथ चर्चा की गई। इनमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 28 योजनाओं को चुस्त बनाया गया तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तमाम पहल की गईं और तमाम अन्य सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है।

केंद्र और राज्यों की साझेदारी वाली योजनाएं शुरू की गईं। इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए मानव पूंजी कायाकल्प के लिए सतत योजना (एसएटीएच) जैसी पहल की गई तो बुनियादी ढांचा विकास के लिए राज्यों के लिए सतत सेवा सहयोग का आगाज हुआ। बेहतर उपचार सुविधाओं के लिए टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के अस्पतालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को हरी झंडी दिखाई गई। विशेष रूप से चिन्हित किए गए 115 जिलों का तकनीक और उपलब्ध सबसे बेहतर प्रक्रियाओं के जरिये कायाकल्प का काम शुरू हुआ तो देश में अंतरराज्यीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विचारों के माध्यम से एकता भाव बढ़ाने के लिए एक भारत-श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाया। कुछ विशेष योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए राज्यों में प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ाया जो व्यवस्था पूर्ववर्ती योजना आयोग से एकदम अलग है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और डिजिटल कायाकल्प जैसे प्रमुख मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन और रैंकिंग की व्यवस्था की गई। बेहतर नतीजों के लिए उन्हें एक दूसरे से होड़ करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है कि वे नए और बेहतर तरीके अपनाकर शानदार परिणाम हासिल कर सकें। मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने और केंद्र के साथ अटके मसलों पर समाधान निकालकर कानूनों को सुसंगत कर नियामकीय सुधारों के लिए

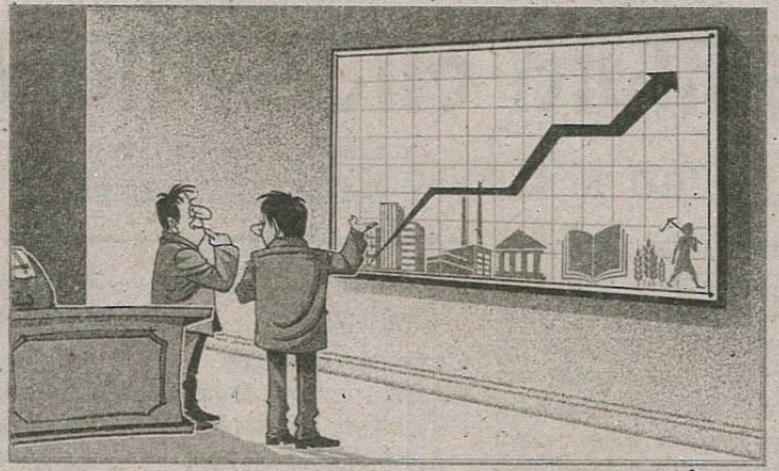

अवधेश राजपूत

भी राज्यों को पूरी मदद दी गई। नीति आयोग ने बीमारू सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सेहत सुधारने में भी अहम भूमिका निभाई। इसके तहत अभी तक एयर इंडिया सहित 30 से अधिक उपक्रमों में रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी जा चुकी है तो खस्ताहाल और नुकसान में चल रहे 15 बीमारू उपक्रमों को बंद करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए भी आयोग ने व्यापक दृष्टिकोण और सतत विकास नजरिये के साथ पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति के ढांचे की राह तैयार की तो गृह मंत्रालय के तत्वाधान में दस द्वीपों के लिए द्वीप विकास एजेंसी यानी आइडीए की स्थापना की और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीआइएस आधारित नियोजन का आगाज किया।

स्वास्थ्य एवं कृषि दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां नीति आयोग ने पुरानी नियोजन प्रक्रिया के उलट क्रांतिकारी सुधारों का सूत्रपात किया। नीति आयोग द्वारा द्वारा तैयार किया नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक चिकित्सा शिक्षा में भारतीय चिकित्सा परिषद के पुराने ढर्रे वाली भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करके नए युग का प्रवर्तन करेगा। इसी तरह आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य भी देश से कुपोषण को मिटाना है। पहले हुए सुधारों के लाभ से वंचित रहे कृषि क्षेत्र में भी अब बंटाईदारी, प्रशासन और विपणन जैसे मोर्चों पर सार्थक सुधार हो रहे हैं।

शासन के स्तर पर भी आमूलचूल बदलाव हो रहे हैं। इस दिशा में सरकारी योजनाओं को सक्षम बनाने के लिए आयोग ने सभी योजनाओं की निगरानी को संस्थागत रूप देने की पहल की है। विकास, निगरानी एवं आकलन कार्यालय इसी मकसद के लिए स्थापित किया गया है। उचित निगरानी समूची बजट प्रक्रिया का कायाकल्प कर देगी। नीति निर्माण में विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए समावेश जैसा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके लिए 34 ज्ञान एवं शोध संस्थानों के साथ करार किए हैं। नीति व्याख्यान शृंखला के तहत वैश्विक बुद्धिजीवी और विचारक विभिन्न नीतिगत मसलों पर नीति निर्माताओं के साथ मंत्रणा कर शासन में नए विचारों और बहस को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह चैंपियन ऑफ चेंज पहल में युवा सीईओ और उद्यमी नीतिगत मसलों पर अपनी राय पेश करते हैं। प्रकाशनों में भी सभी राज्यों, क्षेत्रों के साथ ही सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और स्थानीय निकाय जैसे विषयों को स्थान दिया। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में अपनाए बेहतरीन तौर तरीकों की उचित समय पर जानकारी साझा करने के लिए रीयल टाइम नॉलेज पोर्टल शुरू किए जाने की तैयारी है। वहीं इंडिया एनर्जी पोर्टल जैसे मंचों से नीति आयोग सुशासन और इसके लिए बेहतरीन प्रक्रियाओं की जानकारी और शोध का उचित स्रोत बना है। उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए आयोग ने बड़े बदलाव किए। बहुप्रशंसित अटल इनोवेशन मिशन में बच्चों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए स्कूलों में प्रयोगशाला शुरू कीं तो अटल इनक्यूबेश सेंटर में स्टार्टअप को तेजी से आगे बढ़ने के गुर सिखाए जा रहे हैं। वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन, 2017 के सफल आयोजन से भी आयोग ने दुनिया भर में अपनी सफलता का संदेश दिया। अब महिला उद्यमिता प्रकोष्ठ शुरू किए जाने की भी तैयारी है।

अत्याधुनिक तकनीक अपनाने और उन्हें बढ़ावा देने में भी आयोग अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसमें चाहे नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को विस्तार देने की बात हो या स्मार्ट शहरों में उपयुक्त तकनीक अपनाना। गुड़गांव-नोएडा के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी विचार जारी है। सुशासन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की संभावनाएं भी तलाश रहा है। आंकड़ों की जरूरत पूरी करने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स पोर्टल बनाने की तैयारी भी हो रही है। ऐसे में नीति आयोग ने न केवल अपने नाम के अनुरूप काम किया है, बल्कि भारत के कायाकल्प की कवायद को नई ऊर्जा, जोश और गतिशीलता भी प्रदान की है। यह भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने और सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाने को तत्पर है।

(लेखक नीति आयोग के सीईओ हैं)
response@jagran.com